तिब्बत देश

चीन के लिए भारत की नाक कटाने को तैयार भारत सरकार

भारत पर नगर रखने वाले लोग पिछले साठ साल मे भारत के निरंतर बदलते रूप से बहुत प्रभावित हैं। वे यह देख कर प्रभावित हैं कि एक जमाने में दुनिया भर से मदद मांगने वाला भारत अब दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल होने को तैयार खड़ा है; अनाज से लेकर स्पेस साइंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निर्यातक के रूप में उभर रहा है; डब्लू टी ओ जैसे नाजुक मामलों में अमेरिका जैसी ताकत के आगे छाती ठोंककर खड़े होने की औकात रखता है; और दुनिया भर के विरोध के बावजूद एक न्यूक्लियर ताकत का रूतबा हासिल करता है।

लेकिन यही लोग इस बात से भी हैरान होते हैं कि चीन का नाम सुनते ही यह एशियाई शेर टांगों में दुम दबाकर हकलाने क्यों लगता है? वे लोग यह भी समझना चाहते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेद, वियतनाम और फिलिस्तीन जैसे मामलों में दुनिया भर को आदर्शवाद का पाठ पढ़ाने वाले भारत को अपने दरवाज़े पर तिब्बत में चीनी उपनिवेशवाद के खिलाफ बोलने को क्यों एक शब्द भी नहीं मिलता?

लेकिन पिछले दिनों तो तिब्बती शरणार्थी संगठनों की शांतियात्रा को लेकर भारत सरकार ने दब्बूपने की हद ही कर दी। केंद्र और कुछ राज्य सरकारों की ओछी हरकतों ने भारत को दुनिया भर में निंदा का पात्र बना दिया। इस साल 10 मार्च के दिन तिब्बत पर चीनी कब्जे के खिलाफ तिब्बती जनता की जनक्रान्ति की 49वीं सालगिरह थी। इस मौके पर तिब्बती शरणार्थियों के पांच संगठनों ने एक साझा मंच बनाकर धर्मशाला से भारत–तिब्बत सीमा तक शांतियात्रा करने का फैसला किया। इस पैदल यात्रा की घोषणा जनवरी में ही कर दी गई थी और आयोजकों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि निहत्थे पदयात्रियों का यह अभियान महात्मा गांधी की डांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से प्रेरित है। इसके लिए 100 तिब्बती शरणार्थी स्वयंसेवकों को शामिल किया गया था जिन्होंने लिखित शपथपत्र पर हस्ताक्षर करके कसम खायी थी कि वे किसी भी उकसावे के बावजूद अहिंसक रहेंगे। इन संगठनों में तिबेतन यूथ कांग्रेस भी शामिल थी जिसे चीन सरकार 'आतंकवादी' बताने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाने पर उतारू रहती है।

शांतियात्रियों की योजना हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करते हुए तिब्बत के समर्थन में जनजागरण करने और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत–तिब्बत सीमा में गांधी वादी तरीके से अपने बिछुड़े देश तिब्बत में प्रवेश करने की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि तिब्बत में प्रवेश से रोकने के प्रयास में अगर चीनी सैनिक उन्हें गोली भी मारेंगे तो वे शांति से इन गोलियों का सामना करेंगे। सामान्य भाषा में इसे एक गुलाम देश के युवाओं की गांधीगीरी या अहिंसक छटपटाहट की कहा जाएगा।

मगर दुर्भाग्य से इन अहिंसक युवाओं पर चीनी सेना को गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। चीन सरकार की चापलूसी करने को हरदम उतावले बैठे भारतीय विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों तथा नेताओं ने अपने अतिउत्साह से चीन सरकार के सारे काम आसान कर दिए। संक्षेप में विवरण यह है कि 10 मार्च के दिन पहले तो तिब्बती शांतियात्रियों को पुलिस ने धर्मशाला में ही रोकने की कोशिश की। लेकिन हिमाचल सरकार के कुछ नेताओं के प्रयासों से उन्हें इस शर्त पर आगे जाने दिया गया कि वे हिमाचल–पंजाब सीमा तक शांति को भंग करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। सामान्य कानूनी नजरिए से देखा जाए तो तिब्बती शरणार्थियों समेत भारत में नियमित रूप से रहने वाले हर नागरिक को पूरे भारत में किसी भी सड़क पर चलने का तब तक अधिकार है जब तक वह अशांति न फैलाए या भारत–विरोधी कामों में हिस्सा न ले। 1993 में चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग की यात्रा के समय तिब्बतियों की बिना कारण गिरफ्तारी पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि शरणार्थी होने के बावजूद तिब्बतियों को भारतीय संविधान कई तरह के मूलभूत अधिकार देता है जिनमें सड़क पर शांति से चलने और अपनी राय सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने का अधिकार भी शामिल है।

संयोग से 10 मार्च को शांतियात्रा शुरू होने के बाद तिब्बत के भीतर चीन के खिलाफ अभूतपूर्व आंदोलन शुरू हो गया। तिब्बती प्रदर्शनकारियों पर चीनी सेना की हिंसा ने दुनिया भर में तिब्बत के सवाल को एकदम गर्म कर दिया। लेकिन भारत सरकार हमेशा की तरह चीन को खुश करने के लिए तिब्बती युवाओं की शांतियात्रा को रोकने पर तुली हुई थी। तिब्बत में उथल पुथल की खबरें आते ही 13 मार्च के दिन सभी शांतियात्रियों को डेरा में गिरफ्तार करके यात्रा को रोक दिया गया। उधर तिब्बती आंदोलन ठंडा होने के बजाए जंगल की आग की तरह लगातार फैल रहा था। चीनी सेना की गोलियों से पहले दस दिन के भीतर 150 से ज्यादा तिब्बती मारे गए। बाद में यह संख्या 209 हो गई। आखिर जब पूरी दुनिया में चीन सरकार की थू–थू होने लगी तब भारत सरकार ने विश्व जनमत से डर कर यात्रियों को दो–चार की किस्तों में गुपचुप अंदाज़ में रिहा कर दिया।

लेकिन शांतियात्रा के फिर से शुरू होने पर उत्तराखंड की सरकार पर केंद्र ने दबाव डालकर यात्रा के रास्ते में जैसे अड़ंगे डाले उसने राज्य सरकार और केंद्र दोनों को शर्मसार किया। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से काफी पहले शांतियात्रा के सभी नेताओं को अचानक गिरफ्तार करके दस दिन तक जेल में डाल दिया गया। तब तक शांतियात्रियों की संख्या 360 हो चुकी थी। भूखा रखकर उनका मनोबल तोड़ने के लिए राज्य पुलिस ने उनके तंबू और खाना पानी लेकर चलने वाले दस ट्रकों को भी जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने सड़कों की नाकेबंदी करके शांतियात्रियों के साथ–साथ हाइवे के यात्रियों को भी परेशान किया। लेकिन इन अवरोधों के बावजूद शांतियात्री 110 दिन की पदयात्रा के बाद इनर लाइन तक पहुंचने में कामयाब रहे। वहां प्रशासन ने 27 जून के दिन सभी शांतियात्रियों को पुलिस की बसों में ठूंसकर हिमाचल प्रदेश की तिब्बती बस्ती पाउंटा साहिब में छोड़ दिया।

वैसे तो इस मामले में भारत सरकार की आसान नीति यही होनी चाहिए थी कि शांतियात्रियों को पिथौरागढ़ तक अपनी मर्जी से जाने दिया जाता। रास्ते में राज्यों की पुलिस इस बाद का ध्यान रखती कि पदयात्री किसी तरह की अशांति फैलाने वाला काम न करें और उनके कारण सड़क पर यातायात की व्यवस्था खराब न हो। बाद में पिथौरागढ़ में सुरक्षित भीतरी लाइन पर इन पदयात्रियों को रोक दिया जाता। अगर यात्री जोर जबरदस्ती आगे जाने की कोशिश करते तो कानूनी कार्रवाई करके उन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया जाता या पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर किसी सुरक्षित इलाके में छोड़ दिया जाता। इससे शांतियात्रियों को लंबी यात्रा की तसल्ली रहती, भारत सरकार की जिम्मेवारी भी पूरी होती और चीन को भी संतोष रहता कि किसी ने सीमा नहीं लांघी।

लेकिन दुर्भाग्य से चीन सरकार को खुश करने में जुटी भारत सरकार ने नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सभी मोर्चों पर अपनी भद्द पिटवाई। ऐसे ऐतिहासिक दिनों में जब तिब्बत में उठ खड़े हुए जनांदोलन के कारण पूरी दुनिया की नज़रें तिब्बत और तिब्बतियों पर टिकी हुई थीं, निहत्थे और गांधीवादी रास्ते पर आंदोलन चलाने वाले तिब्बती शरणार्थियों के साथ इस तरह की ज्यादती करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चीनी उपनिवेशवादी सरकार के साथ खड़ा कर लिया। एक ओर तो यह भारत की मानवाधिकार प्रेमी जनता का अपमान है और दूसरी ओर तिब्बती युवा पीढ़ी को इससे यही दुर्भाग्यपूर्ण संदेश जाता है कि सरकारें गांधीगीरी की नहीं बल्कि हिंसा की आवाज सुनती हैं।

– विजय क्रान्ति

फोटो : विजय क्रान्ति

तिब्बत के 209 शहीदों की प्रतीकात्मक शवयात्रा नई दिल्ली में : श्रद्धांजलि

तिब्बत की शांति कब्रिस्तान में पसरी खामोशी के समान है

छह अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने चीन सरकार को सभ्य लोकतांत्रिक व्यवहार की सलाह दी

चीन द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा स्टालिन और माओ के युग के सर्वाधिक खराब क्षणों की याद ताजा कराती है। लेकिन सबसे खतरनाक पहलू है तिब्बत को शेष दुनिया से काटने का प्रयास।

दुनिया की छह चर्चित हस्तियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि तिब्बत में चीनी दमन से स्थापित शांति असल में कब्रिस्तान जैसी शांति है। चीन सरकार को सलाह दी है कि वह तिब्बत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी दमनात्मक कार्रवाई बंद करे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तथा तटस्थ संगठनों को वहां की स्थिति का सच्चा आकलन करने के लिए वहां जाने की छूट दे। इस बयान को जारी करने वाले हैं श्री वैकलेव हेवेल जो चेक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति हैं। आंद्री ग्लुक्समैन जो फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। योहेई सासाकावा एक जापानी जनहितैषी कार्यकर्ता हैं। अल हसन बिन तलाल अरब थॉट फोरम के अध्यक्ष हैं। एफ. डब्ल्यू. डी क्लार्क दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और कारेल श्वार्जनबर्ग चेक गणराज्य के पूर्व मंत्री हैं।

तिब्बत और इसके आसपास के इलाकों में घटित हाल की घटनाएं गंभीर चिंता का कारण हैं। वस्तुतः तिब्बती भिक्षुओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तितर–बितर करने के लिए चीनी अधिकारियों द्वारा उठाये गए कदम की वजह से लोकतांत्रिक जगत में चीन की किरकिरी हुई है। चीन के दमनकारी कदम का ही नतीजा है कि तिब्बतियों के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है, जिसे चीनी सेना कुचलने में जुटी हुई है।

तिब्बतियों के प्रदर्शन के प्रतिक्रियास्वरूप चीनी अधिकारियों ने निरंकुश कार्रवाइयां शुरू कीं, जो 1989 में मध्य और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की समाप्ति से पहले होने वाली ऐसी ही कार्रवाइयों की याद ताजा करती हैं। चीन की निरंकुश गतिविधियों में घरेलू मीडिया पर प्रतिबंध के अलावा चीन स्थित विदेशी मीडिया की खबरों को ब्लैकआउट करना, विदेशी पत्रकारों को वीजा देने इनकार करना और दलाई लामा और उनके सहयोगियों को अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराना शामिल रहा है।

निश्चित तौर पर, चीन सरकार के कुछ प्रतिनिधियों और सरकारी मीडिया द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा स्टालिन और माओ के युग के सर्वाधिक खराब क्षणों की याद ताजा कराती है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सबसे खतरनाक पहलू है तिब्बत को दुनिया के शेष हिस्सों से काटने का मौजूदा प्रयास।

हालांकि यह स्पष्ट है कि चीन सरकार दुनिया को फिर से यह आश्वस्त करने का प्रयास कर रही है कि तिब्बत में शांति और सद्भाव पुनः बहाल हो चुका है। लेकिन म्यांमार, क्यूबा, बेलारुस और कुछ अन्य देशों में इसी तरह की स्थितियों और उसके परिणामों को ध्यान में रखकर हम तिब्बत की शांति को 'कब्रगाह की खामोशी' का नाम भी दे सकते हैं।

तिब्बतियों से निपटने में अधिक से अधिक संयम बरतने की चीन को दी जाने वाली सलाह, जैसा कि दुनिया के कोने–कोने से दी जा रही है, का कोई बेहतर परिणाम शायद ही मिल पाए।

संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ–साथ दुनिया के विभिन्न देशों को व्यक्तिगत तौर पर भी निम्नांकित मांगों पर अमल के लिए चीन सरकार पर दबाव बढाना चाहिए :–

– घटना की व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए तिब्बत और उसके समीपवर्ती प्रांतों में विदेशी मीडिया तथा अंतर्राष्ट्रीय तथ्यान्वेशी मिशनों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए।

– अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का शांतिपूर्वक इस्तेमाल करने वालों को रिहा किया जाए और उन्हें यह आश्वस्त किया जाए कि उनके साथ किसी तरह का उत्पीड़न या गलत सुनवाई नहीं होगी।

– तिब्बती जनता के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बातचीत के प्रयास किये जाएं।

जबतक कि इन स्थितियों पर अमल नहीं किया जाता तबतक अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों के आयोजन पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए।

'वतन की ओर' शांति यात्रा का एक दृश्य : अहिंसा की ताकत

तिब्बती युवाओं की ऐतिहासिक शांतियात्रा

'वतन की ओर कूच' पर भारत सरकार की ओछी नीति और हरकतों ने भारत को हंसी का पात्र बनाया

तिब्बत के स्वतंत्रता आंदोलन में इस साल 10 मार्च के दिन एक नया अध्याय जुड़ गया। शरणार्थी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच काम करने वाले पांच सबसे प्रमुख तिब्बती संगठनों ने एक मंच पर आकर एकसाथ स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने का फैसला किया। इस मंच का नाम ''टिबेटन पीपल्स अपराइज़िंग मूवमेंट'' टीपीयूएम रखा गया है।

इस साल जनवरी में इस साझा मंच का गठन किया गया था जिसमें तिब्बती युवा कांग्रेस, तिबेतन वीमेन एसोसिएशन, चीन सरकार की जेलों में बंद रहे पूर्व राजनीतिक कैदियों के संगठन गू चू सुम, स्टूडेंट्स फार ए फ्री टिबेट और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ टिबेट ने आपस में हाथ मिलाने का फैसला किया। *(तिब्बत–देश के फरवरी–2008 अंक में पृ.–5 पर रिपोर्ट देखें)*

अपने सबसे पहले अभियान के लिए इस संगठन ने धर्मशाला से तिब्बत तक की शांतियात्रा को चुना। इस शांति यात्रा का उद्देश्य गांधीवादी शैली में भारत–तिब्बत सीमा को पार करके चीनी कब्जे में फंसे अपने देश तिब्बत में प्रवेश करना था। तिब्बत में प्रवेश के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को चुना गया। इस शांतियात्रा को 1959 की तिब्बती जनता की जनक्रान्ति की 49वीं वर्षगांठ के दिन 10 मार्च को धर्मशाला से शुरू करने का फैसला किया गया। यात्रा की शुरूआत टीपीयूएम के 100 कार्यकर्ताओं से हुई जो बाद में बढ़ते–बढ़ते 360 हो गई।

लेकिन यात्रा शुरू होने के दो–तीन दिन के भीतर ही तिब्बत में उठ खड़े हुए जन आंदोलन ने न केवल इस शांति यात्रा को एक नया आयाम दे दिया बल्कि इस अभियान के लिए कई नई समस्याएं भी खड़ी कर दीं। 10 मार्च के दिन तिब्बत में ल्हासा में शुरू हुए प्रदर्शन देखते ही देखते ये प्रदर्शन पूरे तिब्बत में फैल गए। इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए चीनी सेना की हिंसा ने 209 से ज्यादा तिब्बतियों की जान ले ली। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और चीन विरोधी वातावरण पैदा हो गया।

एक तरफ चीन सरकार का दबाव और दूसरी ओर तिब्बत के समर्थन में दुनिया भर में पैदा हुआ नया वातावरण –– इस असमंजस में फंसी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अफसरों ने शांति यात्रा के लिए कई तरह के व्यवधान खड़े करके दुनिया भर में भारत को हंसी और निंदा का पात्र बनाया। पहले तो शांति यात्रा के सभी कार्यकर्ताओं को कांगड़ा के बाद डेरा पहुंचने पर गिरफ्तार करके यात्रा को भंग करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस बीच तिब्बत में जंगल की आग की तरह फैलते जनांदोलन और चीनी सेना की हिंसक प्रतिक्रिया ने दुनिया भर में तिब्बत समर्थन की एक ऐतिहासिक लहर पैदा कर दी। ऐसे में भारतीय मीडिया, राजनीतिक दलों और आम लोगों के भारी विरोध को देखते हुए हिमाचल सरकार ने गिरफ्तार शांतियात्रियों को धीरे–धीरे रिहा कर दिया।

इस बीच टीपीयूएम ने शांतियात्रियों का एक नया जत्था तैयार करके हिमाचल–पंजाब सीमा से शांतियात्रा को जारी रखने का फैसला किया। बाद में हिमाचल से रिहा हुए शांतियात्रियों के इस जत्थे ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल के रास्ते भारत–तिब्बत सीमा की तरफ अपना कूच जारी रखा। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के दबाव में आकर उत्तराखंड की सरकार ने शांतियात्रा को भंग करने के लिए कई प्रयास किए। इनमें शांतियात्रियों का रास्ता रोकने, उसके नेताओं को गिरफ्तार करने और उनकी भोजन सामग्री और तम्बू लेकर चलने वाले ट्रकों को पकड़कर भूखा रखने जैसे ओछे हथकंडे भी शामिल थे।

इसके बावजूद शांतियात्रा पिथौरागढ़ पहुचने में कामयाब रही। लेकिन अपने आखिरी हथियार के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भारत–तिब्बत सीमा पुलिस की मदद से पूरे जत्थे को जबरन गाड़ियों में ठूंसकर उन्हे उत्तराखंड की सीमा से बाहर हिमाचल के पाउंटा साहिब में छोड़ दिया। (शांतियात्रा पर और सामग्री अगले अंक में)

–विजय क्रान्ति

एक तरफ चीन सरकार का दबाव और दूसरी ओर तिब्बत के समर्थन में दुनिया भर में पैदा हुआ नया वातावरण –– इस असमंजस में फंसी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अफसरों ने शांति यात्रा के लिए कई तरह के व्यवधान खड़े करके दुनिया भर में भारत को हंसी और निंदा का पात्र बनाया।

तिब्बती जनता के समर्थन में लानझाउ विवि में बुद्धिजीवियों का प्रदर्शन : एकजुटता

कई चीनी बुद्धिजीवियों ने तिब्बती जनता के समर्थन का साहस दिखाया

चीन सरकार को 12–सूत्री सुझाव और तिब्बत नीति पर पुनः विचार करने को कहा

हम जोर देकर अधिकारियों से मांग करते हैं कि सभी तिब्बतियों के साथ राजनीतिक जांच और बदले की भावना से पेश न आयें। पकड़े गए सभी लोगों के साथ न्याय संगत तरीके से पेश आयें और जांच पूरी तरह न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो जिससे सभी पार्टियों को इसमें सन्तोष हो।

तिब्बत में उभरे चीन विरोधी जनांदोलन और उसे कुचलने के लिए चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे दमनचक्र ने न केवल दुनिया के विभिन्न देशों में बल्कि चीन में भी लोगों की आत्मा को झकझोरा है। ऐसे 30 चीनी बुद्धिजीवियों ने अपनी सरकार की इस नीति के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में दलाई लामा के शांति प्रयासों का समर्थन करते हुए तिब्बती जनता के मानवाधिकारों का सम्मान करने की मांग की गई है और चीन सरकार से तिब्बत में निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों और मीडिया को जाने और जांच करने की सुविधा देने की मांग की है।

समाचारों से पता चलता है कि तिब्बत में चीनी सेना और पुलिस ने जिस तरह की बेरहमी तिब्बती प्रदर्शनकारियों पर दिखाई उसके खिलाफ कई चीनी बुद्धिजीवियों ने निजी स्तर पर सर्वोच्च नेतृत्व को पत्र लिखकर विरोध व्यक्त किया। बीजिंग में कई चीनी बुद्धिजीवियों ने स्थानीय विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने वाले तिब्बती छात्रों का खुलकर समर्थन किया। उपरोक्त अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में चीनी लेखक, पत्रकार, प्रोफेसर, इंजिनियर, विचारक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और फोटोग्राफर आदि शामिल हैं। इस संयुक्त बयान को 'तिब्बत–देश' के पाठकों के लिए ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. इस समय चीनी मीडिया के एक तरफा प्रोपेगेंडा से अन्तर–जाति मतभेदों पर असर पड़ रहा है और मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को अधिक बढ़ावा मिल रहा है। इससे राष्ट्रीय एकता के दूरगामी उद्देश्य को हानि पहुंच सकती है। हम उस तरह के दुष्प्रचार को रोकने की मांग करते हैं।

2. हम दलाई लामा की शान्ति अपील का समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि जातिगत मतभेद को शान्ति और अहिंसा के सिद्वान्तों से निपटने की आवश्यकता है।

3. चीन सरकार का यह दावा है कि 'उसके पास पर्याप्त तथ्य हैं जो यह साबित कर सकें कि ये घटनाएं दलाई गुट द्वारा पहले से सुनियोजित और सावधानी से रचे गए षडयंत्र के तहत की गई हैं।' हमें आशा है कि सरकार उन तथ्यों को बतायेगी। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विरोध और अविश्वसनीय दर्षष्टिकोण को बदलने के लिए हम यह सुझाव रखते हैं कि सरकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ को आमन्त्रित कर इस घटना के कारणों और मरने वालों की संख्या को लेकर स्वतन्त्र जांच करवायें।

4. हमारी सोच में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस तरह की असांस्कृतिक भाषा का प्रयोग जिसमें दलाई लामा को 'भिक्षु के वेश में भेड़िया' और 'मानवी चेहरे के साथ एक दुष्ट आत्मा और एक हिंसक पशु का हृदय' कहा गया है जो न तो इस स्थिति के अनुकूल है और न इससे चीन सरकार की छवि में कोई सुधार होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि क्योंकि चीन सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए हमारा यह मानना है कि चीन प्रशासन को इस ढंग से कार्य करने चाहिएं जिससे वह आधुनिक सभ्यता के मापदण्ड के साथ खड़ा हो सके।

5. हमने यह देखा है कि जब 14 मार्च को ल्हासा में हिंसा घटी तब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नेताओं ने यह दावा किया कि ''उनके पास पर्याप्त तथ्य हैं जो यह साबित कर सकें कि इन घटनाओं को पूर्वनियोजित तरीके से और सावधानी से दलाई गुट द्वारा किया गया है''। इससे यह साफ है कि उन्हें इस तरह की घटनाओं की सूचना पहले से ही थी और यह जानते हुए भी इसे फैलने से रोकने के कोई कदम नहीं उठाये गए। यदि इसमें उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कोई लापरवाही की है तो इसकी जांच होनी चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए।

6. यदि अन्त में यह स्पष्ट होता है कि यह घटना पूर्व में सुनियोजित और सावधानी से नहीं की गई थी बल्कि मात्र एक घटना के कारण यह ज्यादा भड़की तो सरकार को उन लोगों तक पहुंचना

चाहिए जो इसमें शामिल थे और जिन्होंने चीनी सरकार को गुमराह करने का षड़यन्त्र रचा था। उन्हें इस घटना से सीख भी लेनी चाहिए ताकि वे भविष्य में इस तरह की स्थिति से निपट सकें।

7. हम जोर देकर अधिकारियों से मांग करते हैं कि तिब्बतियों के साथ वे राजनीतिक जांच और बदले की भावना से पेश न आयें। पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ जांच न्याय संगत, न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो जिससे सभी पार्टियों को इसमें सन्तोष हो।

8. हम चीनी सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया को तिब्बत में जाकर स्वतन्त्र इन्टरव्यू और रिपोर्ट लिखने की आज़ादी दे। हम समझते हैं कि जिस तरह से समाचारों पर रोक लगाई गई है उससे न तो चीनी जनता को लाभ होगा और न अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सच्चाई पता लगेगी। बल्कि इससे चीन सरकार की विश्वसनीयता को ही हानि पहुंचेगी। यदि सरकार के पास तथ्यपूर्ण स्थिति की सूचना उपलब्ध हो तो उसे किसी का सामना करने से भय नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार की तरफ अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की अविश्वसनियता को समाप्त करने के लिए हमें एक पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

9. हम चीनी जनता और बाहरी मुल्कों में रह रहे सभी चीनियों से अपील करते हैं कि वे शान्त एवं सहानुभूति अपनाते हुए ताज़ा स्थिति पर अपना दृष्टिकोण बनाएं। कट्टर राष्ट्रवाद को अपनाने से हमें केवल अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की निन्दा ही प्राप्त हो सकती है और इससे चीन की अन्तर्राष्ट्रीय छवि को हानि पहुंच सकती है।

10. सन् 1989 से प्रारम्भ हुआ प्रदर्शन केवल ल्हासा तक सीमित था जबकि इस समय यह प्रदर्शन पूरे तिब्बत में फैल गया है। भयानक होती जा रही यह स्थिति साफ बताती है कि कहीं न कहीं तिब्बत के मसले को निपटने में गम्भीर गलतियां हुई हैं। सम्बद्ध सरकारी विभागों को इस विषय पर मन्थन करने की आवश्यकता है, गलतियों को जांचने और असफल राष्ट्रीय नीतियों को मूलभूत तरीके से सुधारने की दिशा में बदलाव किया जाना जरूरी है।

11. भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार को धार्मिक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी चाहिए जिसका चीनी संविधान में प्रावधान रखा गया है। इससे तिब्बती जनता अपने कष्टों और आशाओं को व्यक्त कर पायेगी और समस्त नागरिक सरकार की राष्ट्रीय नीति के विषय में गलतियां समझकर सुझााव दे सकेंगें।

12. हम यह मानते हैं कि हमें शत्रुता को मिटाना चाहिए और राष्ट्रीय एकजुटता को बनाना चाहिए जिससे नागरिकों के बीच विभाजन न हो। जो देश अपनी सीमाओं को विभाजित करने से रोकना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम अपने नागरिकों को विभाजित होने से रोकना चाहिए। इसलिए हम अपने राष्ट्र के नेताओं से अपील करते हैं कि वह दलाई लामा के साथ सीधा सम्वाद करें। हमें आशा है कि चीन और तिब्बती जनता के बीच हुई गलतफहमियो को मिटाया जाएगा और आपसी रिश्तों को बढ़ावा दिया जाएगा और अन्ततः हम एकता बनाये रखेंगे। सरकारी विभाग एवं लोकप्रिय संगठन अथवा धार्मिक प्रतिनिधियां को इस कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।

हस्ताक्षरकर्ता :

1. वांग ली शोंग (बीजिंग, लेखक),
2. ल्यू जेयावो (बीजिंग, फ्रीलांस लेखक),
3. ज़ंग जूंआ (बीजिंग, संविधान के विद्वान),
4. शा येसिंग (शंघाई, चीनी–मुस्लिम लेखक),
5. यू हाऊचेंग (बीजिंग, न्यायकर्ता),
6. दिंग ज़िलिंग (बीजिंग, प्रोफेसर),
7. जियांग पेकूंग (बीजिंग, प्रोफेसर),
8. यू जी (बीजिंग, लेखक),
9. सुन वेंगांग (शांगदोंग, प्रोफेसर),
10. रैन यून फी (सिचुआन, सम्पादक, तूजिया नागरिक),
11. पू ज़िख्यां (बीजिंग, वकील).
12. तेंग ब्याओ (बीजिंग, वकील एवं विद्वान),
13. लियो ईयू (सिचुआन, लेखक),
14. वॉग कीसिंग (बीजिंग, लेखक).
15. ज़ांग सियांगलिंग (बीजिंग, इंजीनियर),
16. जू जूई (बीजिंग, शोधकर्ता).
17. ली जुन (गांसू, फोटोग्राफर),
18. गाओ यू (बीजिंग, पत्रकार),
19. वॉग देवांग (बीजिंग, फ्रीलांस लेखक).
20. जाओ दागोंग (शिंनजिन, फ्रीलांस लेखक),
21. जियांग दानवेन (शंघाई, लेखक).
22. लियू ई (गांसू, पेंटर),
23. जू हूई (बीजिंग, लेखक),
24. वॉग ताईनचेक (बीजिंग, विद्वान),
25. वेन केजियांग (हांगजू, फ्रीलांस लेखक),
26. ली हाई (बीजिंग, फ्रीलांस लेखक),
27. तियान योंगदे (भीतरी मंगोलिया, लोक मानवाधिकार कार्यकर्ता),
28. जॉग एजोंग (हांगजाऊ, पत्रकार),
29. लियू इमिंग (हूवे, फ्रीलांस लेखक),
30. लियू दी (बीजिंग, फ्रीलांस लेखक)

सन् 1989 से प्रारम्भ हुआ प्रदर्शन केवल ल्हासा तक सीमित था जबकि इस समय यह प्रदर्शन पूरे तिब्बत में फैल गया है। भयानक होती जा रही यह स्थिति साफ बताती है कि कहीं न कहीं तिब्बत के मसले को निपटने में गम्भीर गलतियां हुई हैं। सम्बद्ध सरकारी विभागों को इस विषय पर मन्थन करने की आवश्यकता है, गलतियों को जांचने और असफल राष्ट्रीय नीतियों को मूलभूत तरीके से सुधारने की दिशा में बदलाव किया जाना जरूरी है।

फोटो : विजय क्रान्ति

26 नोबेल विद्वानों ने चीन की निंदा की

दलाई लामा के खिलाफ ओछा अभियान बंद करने और हिंसक कार्रवाई रोकने की मांग

21 मार्च विश्व भर के 26 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने तिब्बती प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चीन की हिंसक कार्रवाई की निंदा करते हुए चीन सरकार से संयम बरतने का अनुरोध किया है। 20 मार्च के दिन एक संयुक्त बयान में इन विद्वानों ने चीन सरकार के उस अभियान की भी निंदा की है जिसके तहत शांति नोबेल पुरस्कार विजेता परमपावन दलाई लामा को बदनाम किया जा रहा है।

अपने इस बयान में नोबेल विजेताओं ने कहा है कि चीन सरकार जानबूझकर उनके साथी नोबेल विद्वान दलाई लामा के खिलाफ ओछा अभियान चला रही है जबकि दलाई लामा चीनी दावों के बावजूद तिब्बत को चीन से अलग करने के लिए नहीं बल्कि तिब्बत के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चीन सरकार से अपील की है कि वह दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करे ताकि तिब्बत की समस्या का एक शांतिपूर्ण और आपसी सहमति वाला हल निकाला जा सके।

नोबेल विजेताओं ने कहा है कि चीन सरकार जानबूझकर उनके साथी नोबेल विद्वान दलाई लामा के खिलाफ ओछा अभियान चला रही है । उन्होंने चीन सरकार से अपील की है कि वह दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करे ताकि तिब्बत की समस्या का एक शांतिपूर्ण और आपसी सहमति वाला हल निकाला जा सके।

इस बयान पर जिन नोबेल विजेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं वे हैं:

अलेक्सेई आब्रिकोसोव, फिज़िक्स (2003)
पीटर आग्रे, कैमिस्ट्री (2003)
बारूज़ बेनासेर्राफ, मैडिसिन (1980)
ग्युंटेर ब्लोबेल, मैडिसिन (1999)
अरविड कार्लसन, मैडिसिन (2000)
जॉन क्योत्ज़े, साहित्य (2003)
पॉल जे क्रूत्ज़ेन कैमिस्ट्री (1995)
क्लाइव डब्लू जे ग्रेंगेर, अर्थशास्त्र (2003)
पॉल ग्रीनगार्ड, मैडिसिन (2000)
एव्रॉम हेर्शको, कैमिस्ट्री (2004)
रोल्ड हॉफमैन, कैमिस्ट्री (1981)
जॉन ह्यूम, शांति (1998)
ब्रायन डी जोसेफ़न, फिजिक्स (1973)
एरिक आर कैंडेल, मैडिसिन (2000)
रॉजेर कॉर्नबेर्ग, कैमिस्ट्र (2006)
फ़िन ई किडलैंड, अर्थशास्त्र (2004)
इर्विन नेहेर, मैडिसिन (1991)
जॉन सी पोलान्यी, कैमिस्ट्री (1986)
एच डेविड पोलित्ज़र, फिजिक्स (2004)
रिचर्ड जे रॉबर्ड, मैडिसिन (1993)
फिलिप ए शार्प, मैडिसिन (1993)
जेंस सी स्काउ, कैमिस्ट्री (1997)
वोल सोयिंका, साहित्य (1986)
ऐली वीज़ेल, शांति (1986)
टार्सटेन एन वीज़ेल, मैडिसिन (1981)
बैट्टी विलियम्स, शांति (1976)

तिब्बती लेखकों की बिना शर्त रिहाई की अपील

धर्मशाला, धर्मशाला के निर्वासित तिब्बती लेखकों के संगठन 'तिबेतन राइटर्स एब्रोड पेन सेंटर' ने तिब्बत की चीनी जेलों में बंद तिब्बती लेखकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग के लिए मोमबत्तियां जलाकर रतजगा किया। यह संगठन दुनिया भर के लेखकों के संगठन 'इंटरनेशनल पेन' का सदस्य है।

यह रतजगा तिब्बती लेखिका डोल्मा कयाब को दस साल जेल की सजा दिए जाने के विरुद्ध अभियान का ही एक हिस्सा है। डोल्मा को मार्च 2005 में गिरफ्तार किया गया था और 16 सितम्बर 2005 को उन्हें सजा सुनाई गयी। उल्लेखनीय है कि डोल्मा की गिरफ्तारी को उनकी अप्रकाशित पुस्तक 'द रेस्टलेस हिमालया' से जोड़कर देखा जाता है।

तिबेतन पेन सेंटर के सदस्यों ने यह भी कहा कि वे तिब्बत में हाल ही में अन्य कई लेखकों को हिरासत में लिए जाने का भी विरोध करते हैं। संगठन ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 19 के तहत इन लेखकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की भी मांग की है। इस समझौते पर चीन सरकार ने 1998 में हस्ताक्षर किए थे।

संगठन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है, ''हम तत्काल आश्वासन चाहते हैं कि उन लेखकों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और चीनी अधिकारियों से यह अपील करते हैं कि हिरासत के दौरान उनके मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए, एवं उन्हें अपने परिजनों, एवं वकीलों से मिलने तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा हासिल करने की अनुमति दी जाए।''

संगठन का आरोप है कि तिब्बती लेखकों द्वारा लिखे गये साहित्य को चीनी अधिकारियों ने प्रतिबंधित कर दिया, जब्त कर लिया और जला डाला। तिब्बती लेखकों द्वारा तैयार किये गये ब्लॉगों को बंद करा दिया गया है और उनके लेखकों को गिरफ्तार कर जल में डाल दिया गया है।

संगठन ने कहा है कि दावा ग्याल्त्सेन, जाम्पेल ग्यात्सो, वेन. नावांग फुलचुंग, ताशी ग्याल्त्सेन, लोबसांग धरगे ऐसे तिब्बती लेखकों में शामिल है, जो कम से कम पांच साल से लेकर 19 साल तक की सजा काट रहे हैं। त्सेरिंग वोसेर, वेन. रिनचेन सांगपो और कालसांग ग्यामत्सो जैसे प्रमुख लेखक भी नजरबंद जैसी स्थिति में रह रहे हैं।

ओलम्पिक शहर जाने वालों की पृष्ठभूमि की गुप्त जांच करेगा चीन

लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र डेली मेल के अनुसार चीन सरकार पर बीजिंग में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों, अधिकारियों और पत्रकारों की पृष्ठभूमि की गुप्त जांच कराने का आरोप है। समाचारपत्र का कहना है कि चीन सरकार इस बात से चिंतित है कि ओलंपिक के दौरान इनमें से कई लोग अपनी हरकतों से चीन सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसलिए वह वैसे लोगों को बीजिंग पहुंचने से रोकना चाहती है जो चीन की नीतियों का विरोध कर सकते हैं।

यूरोपीय पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव सांसद एडवार्ड मैकमिलन स्कॉट ने दावा किया है कि चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें इस बात का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है कि किस प्रकार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए। मंत्रालय ने चीन का विरोध करने वालों की 43 श्रेणियां बनायी है।

दस्तावेज के अनुसार, तिब्बत की आजादी के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकने वाले एथलीटों, अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के सदस्यों, पत्रकारों, प्रायोजकों या अतिथियों को ओलम्पिक से बाहर रखना जरूरी हो चुका है।

ऐसी भी खबर है कि जांच के दायरे में अगले ओलम्पिक खेलों के मेजबान शहर लंदन के प्रतिनिधि भी होंगे। वर्ष 2012 में होने वाले लंदन ओलम्पिक खेलों के अध्यक्ष लॉर्ड कोए और लंदन के मेयर केन लिविंगस्टोन को भी चीन पर अपने राजनीतिक विचारों के लिए जांच के दायरे से गुजरना होगा।

1.3 अरब चीनी नागरिकों की निगरानी के लिए जिम्मेदार बीजिंग स्थित सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय कथित रूप से यह सूची तैयार कर रहा है कि कैसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाए। मंत्रालय ने इसमें धार्मिक संगठनों और आतंकवादी संगठनों के सदस्यों के अलावा मीडिया का वह वर्ग भी शामिल है जिससे ओलम्पिक खेलों को खतरा है।

ग्रीस ओलंपिया स्टेडियम में मशालयात्रा की शुरूआत पर तिब्बती प्रदर्शनकारी : मानवाधिकारों के लिए

'चीन के दुश्मन' शीर्षक वाली श्रेणी में उन लोगों के परिजनों को शामिल किया गया है जो थिएन अनमेन स्क्वेयर जैसी घटनाओं और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारे गये हैं। इस श्रेणी में विदेश की चीन विरोधी ताकतें और वैसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने 'सामाजिक स्थिरता तहस–नहस की'। 'अलगाववादियों' की सूची में दलाई लामा के नेतृत्व वाली निर्वासित तिब्बत सरकार, इससे संबद्ध संगठनों के सदस्य तथा ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने चीन को विखंडित करने के लक्ष्य से विरोध–प्रदर्शनों और अन्य अलगाववादी गतिविधियों में हिस्सा लिया हो।

चीन सरकार ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा है। उसकी योजना वैसे पत्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाने की है जो चीन के दुश्मन देशों के हों या कम्युनिस्ट विरोधी लेख प्रकाशित करने वाले मीडिया संगठनों से जुड़े हों और जिन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार पर तोहमतें लगाई हैं।

चीन सरकार की लंबे समय से आलोचना करने वाले श्री मैकमिलन स्कॉट ने कहा है कि उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि ये जानकारियां बिल्कुल सही हैं और वह इस पर भरोसा करते हैं।

चीनी के प्रतिबंधित धार्मिक संगठन फालुन गोंग के प्रवक्ता एरपिंग झांग ने कहा, ''ये दस्तावेज चीनी सुरक्षा ब्यूरो से उड़ाये गये हैं। फालुन गोंग की साधना करने वाले कुछ लोग सुरक्षा ब्यूरो में तैनात हैं। उन लोगों ने यह जानकारी पिछले वर्ष भेजी थी और हम जानते हैं कि यह बिल्कुल सही दस्तावेज है।''

दस्तावेज के अनुसार, तिब्बत की आजादी के समर्थन में प्रदर्शन कर सकने वाले एथलीटों, अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के सदस्यों, पत्रकारों, प्रायोजकों या अतिथियों को ओलम्पिक से बाहर रखना जरूरी हो चुका है। जांच के दायरे में अगले ओलम्पिक खेलों के मेजबान शहर लंदन के प्रतिनिधि भी होंगे।

कैमरे की

1. 17 अप्रैल को दिल्ली में तिब्बत समर्थकों की समांतर 'तिब्बत मानवाधिकार
2. तिब्बत की घटनाओं पर नेपाल में तिब्बतियों के प्रदर्शनों को कुचलने के
3. अपने तिब्बती भाई–बहनों के समर्थन में दिल्ली के तिब्बती समाज ने जंत
4. 25 अप्रैल के दिन मास्को में तिब्बत की जनता के समर्थन में रूसी तिब्बत
5. नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 'तिब्बत मानवाधिकार मशाल' रैली में तिब्ब
6. जंतर मंतर पर 'तिब्बत मानवाधिकार मशाल' रैली को भारतीय राजनेताओं
7. तिब्बत की घटनाओं से आंदोलित तिब्बती शरणार्थियों ने प्रभावी तरीके से
8. तिब्बत में चीनी गोलियों से शहीदों के सम्मान में दिल्ली में 108 तिब्बतियों
9. तिब्बत के भीतर चीनी कब्जे के खिलाफ उठी जनक्रान्ति के समर्थन में ए
10. तिब्बत के आजादी के आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारत के सभी

आंख से

र मशाल' रैली ने बीजिंग–ओलंपिक टार्च को फीका कर दिया।

लिए नेपाल सरकार ने पुलिस का भारी प्रयोग किया।

र मंतर पर दो महीने लंबा धरना किया। धरने में शांति यात्री ।

त समर्थकों के प्रदर्शन से उलझती रूसी पुलिस।

त की पुरानी मित्र और समर्थक सुश्री जया जेटली।

ं का भारी समर्थन मिला। रैली में सांसद श्री किरण रिजुजू।

अपनी एकजुटता दिखाई। धर्मशाला में ऐसा एक प्रदर्शन।

ों ने अपना सिर मुंडवा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

क प्रदर्शन के दौरान अपनी बांह पर तिब्बती झंडा बनवाता एक बच्चा।

वर्गों के लोगों ने रैलियों में भाग लिया। जंतर मंतर की एक रैली में भारतीय मित्र।

1 और 4 के अलावा अन्य सभी फोटो : विजय क्रान्ति

फोटो : विजय क्रान्ति

नई दिल्ली जंतर मंतर पर भारतीय समर्थक : एकजुटता का प्रदर्शन

भारत भर में समर्थन का सैलाब उभरा

तिब्बती जनता के समर्थन में भारतीय संगठनों और शरणार्थी समाज की एकजुटता

तिब्बत के पांच प्रमुख संगठनों ने धर्मशाला से तिब्बत तक की शांति यात्रा शुरू की। यात्रा की शुरूआत तिब्बती युवा कांग्रेस, तिबेतन वीमेन एसोसिएशन, गू चू सुम, स्टूडेंट्स फार ए फ्री टिबेट और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ टिबेट के 100 कार्यकर्ताओं से हुई।

10 मार्च – तिब्बती जनक्रांति की 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और दुनिया भर में तिब्बत समर्थक संगठनों ने तिब्बत के प्रति एकजुटता दिखाई गई। भारत में मुख्य प्रदर्शन धर्मशाला में हुआ। इसके अलावा तिब्बत के शरणार्थी संगठनों और भारत के तिब्बत समर्थक संगठनों ने दिल्ली, वर्धा, नागपुर, शिमला, जम्मू, चेन्नै, बालकुप्पे, जयपुर, रीवा, बोमडीला, रांची, भोपाल, पटना, चंडीगढ़, मनाली, कालिंपोंग, बंगलूरू और मैसूर समेत कई जगह प्रदर्शन किए। लेकिन 14 मार्च से तिब्बत में तिब्बत में शुरू हुए ऐतिहासिक जनांदोलन के समर्थन में प्रदर्शनों का सिलसिला बहुत प्रभावशाली रहा।

10 मार्च – तिब्बत के पांच प्रमुख संगठनों ने धर्मशाला से तिब्बत तक की शांति यात्रा शुरू की। यात्रा की शुरूआत तिब्बती युवा कांग्रेस, तिबेतन वीमेन एसोसिएशन, गू चू सुम, स्टूडेंट्स फार ए फ्री टिबेट और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ टिबेट के 100 कार्यकर्ताओं से हुई। बाद में भारत सरकार की बार–बार बदलती नीतियों के कारण हर दिन नाटकीय होती इस यात्रा में यात्रियों की संख्या 360 हो गई। यात्रा शुरू होने के दो–तीन दिन के भीतर तिब्बत में उठ खड़े हुए जन आंदोलन ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इस स्थिति से हड़बड़ायी भारत सरकार ने शांति यात्रा के सभी कार्यकर्ताओं को कांगड़ा के बाद डेरा पहुंचने पर हिरासत में ले लिया। बाद में भारतीय जनमानस के विरोध को देखते हुए शांति यात्रियों को रिहा करके यात्रा जारी करने की अनुमति दे दी गई।

13 मार्च – भारत तिब्बत मैत्री संघ की अहमदाबाद में सार्वजनिक सभा और प्रदर्शन।

14 मार्च – इंडियन मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में तिब्बत की मौजूदा स्थिति पर आयोजित सेमिनार में वरिष्ठ पत्रकार और तिब्बतशास्त्री श्री विजय क्रान्ति ने व्याख्यान दिया।

14 मार्च – अपने देशवासियों के ऐतिहासिक जनांदोलन में उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए लगभग पांच हजार तिब्बतियों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन शुरू किया जो लगातार दो महीने तक चला।

15 मार्च – तिब्बती युवाओं ने मेट्रो नेशन टीवी चैनेल पर तिब्बत की स्थिति पर बहस में भाग लिया।

17 मार्च – तिब्बत के जन आंदोलन के प्रति भारत के तिब्बत समर्थक सर्वदलीय संसदीय मंच ने अपने समर्थन की घोषणा एक प्रेस कांफ्रेंस में की।

17 मार्च – तिब्बती जनता के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए भारत–तिब्बत मैत्री संघ ने वाराणसी में पदयात्रा का आयोजन किया।

18 मार्च – तिब्बती जनता के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए विदेह समाज ने गुड़गांव में अनशन का आयोजन किया।

19 मार्च – भारत–तिब्बत मैत्री संघ ने अहमदाबाद में तिब्बत के समर्थन में प्रदर्शन किया।

19 मार्च – नई दिल्ली में तीन मूर्ति चौक पर विश्व हिंदू परिषद, एच एम एस और एस आर एस ने प्रदर्शन करके तिब्बती जनता के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

20 मार्च – भारत तिब्बत मैत्री संघ ने तिब्बत की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया।

20 मार्च – तिब्बत की भीतरी स्थिति और भारत सरकार की नीतियों के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भारत–तिब्बत सहयोग मंच और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रधान श्री के एस सुदर्शन ने एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित किया।

20 मार्च – नागपुर में तिब्बती जनता के आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए भारत–तिब्बत सहयोग मंच ने पदयात्रा का आयोजन किया।

21 मार्च – भारत–तिब्बत मैत्री संघ ने नागपुर में अर्जुन मोड़ पर एक पदयात्रा का आयोजन किया।

24 मार्च – नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भारत के सभी तिब्बत समर्थक संगठनों ने एक संयुक्त प्रदर्शन में भाग लिया। इसमें वहां 14 मार्च से क्रमिक अनशन पर बैठे तिब्बती समाज ने भी भाग लिया।

24 मार्च – जयपुर में हिमालय परिवार द्वारा तिब्बती

जनता के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन।

24 मार्च – एन सी टी सी कार्यकर्ताओं ने तिब्बत के समर्थन में नागपुर में एक विशाल रैली निकाली।

28 मार्च – भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के फोरम ने न्यू चैबर्स में तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर एक सेमिनार का आयोजन किया और तिब्बती जनता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया ।

28 से 31 मार्च – भारत–तिब्बत मैत्री संघ के कार्यकर्ताओं ने तिब्बती जनता के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में जंतर मंतर पर दैनिक अनशन किया।

29 मार्च – भारत तिब्बत मैत्री संघ ने लखनऊ में तिब्बत के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया।

29 मार्च – भारत तिब्बत मैत्री संघ के कार्यकर्ताओं ने मैसूर में एक जनसभा की और तिब्बत के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ज्योति यात्रा की।

31 मार्च – वाराणसी में तिब्बत की स्थिति के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए भारत–तिब्बत मैत्री संघ ने एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया और तिब्बत संबंधी डाक्युमेंट्री फिल्में दिखायीं।

31 मार्च – नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भारत–तिब्बत मैत्री संघ के कार्यकर्ताओं का एक दिन का अनशन।

5 अप्रैल – पूर्व राजदूत श्री दलीप मेहता ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ''तिब्बत में हाल की घटनाएं और भारत के लिए पेचीदगियां' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

6 अप्रैल – भारत तिब्बत सहयोग मंच ने लखनऊ में तिब्बत के समर्थन में एक सार्वजनिक सभा की।

7 अप्रैल – नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में भारतीय जनता पार्टी ने तिब्बत के समर्थन में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया।

7 अप्रैल – तिब्बत पर चीन के कब्जे के कारण भारत की सुरक्षा पर आए खतरे के बारे में बारे में विश्लेषण के लिए दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार और तिब्बती मामलों के विशेषज्ञ श्री विजय क्रान्ति थे।

12 अप्रैल – नई दिल्ली के आनंद नगर में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने सैकेंडरी स्कूल में अध्यापकों के लिए तिब्बत पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

14 अप्रैल – नई दिल्ली के संसद मार्ग पर डा. अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया गया जिसमें तिब्बत पर चीनी कब्जे के कारण भारत की सुरक्षा पर आए खतरे के बारे में उनके विचारों पर चर्चा की गई।

15 अप्रैल – भारत तिब्बत सहयोग मंच ने पटना में तिब्बत विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया।

16 अप्रैल– भारत तिब्बत मैत्री संघ ने जवाहर लाल नेहरू विवि में तिब्बत के बारे में सम्मेलन किया।

17 अप्रैल – नई दिल्ली से बीजिंग ओलंपिक की मशाल के गुजरने के मौके पर भारत के तिब्बत समर्थक संगठनों ने समांतर तिब्बती ओलंपिक मशाल का जलूस निकाला। गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना के बाद धर्मज्योति को तिब्बती मशाल रैली को सौंपा गया। जंतर मंतर पर एक अभूतपूर्व रैली में इसका स्वागत किया गया। तिब्बती संगठनों ने तिब्बत में चीनी अत्याचारों की झांकियां पेश कीं। भारतीय मीडिया में इस समांतर रैली के प्रचार के सामने ओलंपिक मशाल की सरकारी रैली बुरी तरह फीकी पड़ गई।

19–20 अप्रैल – मैसूर में भारत तिब्बत मैत्री संघ ने फोटो प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन किया।

22 अप्रैल – नई दिल्ली के पहाड़गंज में यूनाइटेड एंटी टेररिस्ट आर्गेनाइजेशन ने तिब्बत के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

25 अप्रैल – भारत तिब्बत सहयोग मंच ने शिमला में तिब्बती शहीदों की याद में ज्योति यात्रा और प्रेस कान्फ्रेंस का अयोजन किया।

26 अप्रैल – भारत तिब्बत सहयोग मंच ने धर्मशाला में तिब्बत के समर्थन में एक प्रेस कान्फ्रेंस की।

25–27 अप्रैल – अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत तिब्बत समर्थक संगठनों की केंद्रीय संचालन समिति आईटीएसएन की एशियाई क्षेत्रीय कान्फ्रेंस का आयोजन धर्मशाला में किया गया।

28–30 अप्रैल – हिमालय परिवार का जयपुर में तिब्बत के समर्थन में एक विशेष कार्यक्रम।

28 अप्रैल – हिमालय परिवार की तिब्बत पर जयपुर में पूजनीय बाबा उमा कैलाशपति ठाकर जी से भेंट।

4 मई – चंडीगढ़ में तिब्बत के समर्थन में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने कार्यक्रम किया।

5 मई – भारतीय बुद्धिजीवियों की नई दिल्ली में मंडी हाऊस से जंतर मंतर तक तिब्बत समर्थक पदयात्रा।

9 मई – तिब्बत पर भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों की भविष्य की कार्रवाइयों पर विचार के लिए कोर ग्रुप फॉर तिबेतन कॉज़ की नई दिल्ली में विशेष बैठक।

12 मई – तिब्बती जनता के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए अखिल भारतीय संत एकता आंदोलन परिषद ने नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक सम्मेलन का आयोंजन किया।

तिब्बत के शरणार्थी संगठनों और भारत के तिब्बत समर्थक संगठनों ने दिल्ली, वर्धा, नागपुर, शिमला, जम्मू, चेन्नै, बालकुप्पे, जयपुर, रीवा, बोमडीला, रांची, भोपाल, पटना, चंडीगढ़, मनाली, कालिंपोंग, बंगलूरू और मैसूर समेत कई जगह प्रदर्शन किए। लेकिन 14 मार्च से तिब्बत में तिब्बत में शुरू हुए ऐतिहासिक जनांदोलन के समर्थन में प्रदर्शनों का सिलसिला बहुत प्रभावशाली रहा।

स्टीवन स्पीलबर्ग : नैतिक साहस, राजनीतिक फैसला

स्टीवन स्पीलबर्ग और उमा थुर्मान का बीजिंग ओलम्पिक बहिष्कार का फैसला

चीन की मानवाधिकार विरोधी नीतियों ने बहिष्कार के लिए मजबूर किया

मुझे अपना समय और ऊर्जा ओलम्पिक समारोहों पर खर्च न कर दार्फुर में मानवता के खिलाफ हो रहे अपराधों के खात्मे में मदद के लिए खर्च करनी चाहिए। मैंने ओलंपिक समारोहों में बतौर सलाहकार अपनी भागीदारी खत्म करने फैसला कर लिया है।

लंदन हॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता–निर्देशक एवं पटकथा लेखक स्टीवन स्पीलबर्ग ने घोषणा की है कि वह दार्फुर में होने वाले उत्पीड़न में चीन की भूमिका के विरोध में इस वर्ष आयोजित होने वाले बीजिंग ओलम्पिक से अलग रहेंगे। उनके इस फैसले के बाद उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अमरीकी अभिनेत्री उमा थुर्मन भी चीन में मानवाधिकार की स्थिति पर चिंता जताने वाली हस्तियों में शामिल हो गयीं।

श्री स्पीलबर्ग को अगस्त में होने वाले ओलम्पिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोहों में कला सलाहकार की भूमिका निभानी थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे। श्री स्पीलबर्ग के इस फैसले से चीन को गहरा धक्का लगा है।

चीन सुडान का मित्र देश है और वहां से तेल खरीद के बदले में वहां की सरकार को अपने हथियार बेचता है। सुडान के दक्षिणी हिस्से में स्थित दार्फुर में हुए जनसंहारों के लिए वहां की सरकार की दुनिया भर में निंदा हो रही है। लेकिन इस कारण इस अफ्रीकी देश पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर चीन सरकार ने वीटो लगाने की भी धमकी दी है।

श्री स्पीलबर्ग ने अपने बयान में कहा, ''मुझे लगता है कि मेरी आत्मा मुझे इस काम के लिए इजाजत नहीं देगी।''

उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर मुझे अपना समय और अपनी ऊर्जा ओलम्पिक समारोहों पर खर्च न कर दार्फुर में मानवता के खिलाफ हो रहे अपराधों के खात्मे में मदद के लिए खर्च करनी चाहिए। श्री स्पीलबर्ग ने कहा, ''मैंने बीजिंग ओलम्पिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोहों में बतौर सलाहकार अपनी भागीदारी खत्म करने की औपचारिक घोषणा करने का फैसला कर लिया है।''

सुडान सरकार के लिए चीन का समर्थन पहली बार दुनिया के समक्ष उस वक्त आया था, जब उसने दार्फुर में वहां की सरकार समर्थित जंजावीर मिलिशिया के हाथों अनेक लोगों के मारे जाने के बाद 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध प्रस्तावों पर वीटो करने की धमकी दे डाली थी।

श्री स्पीलबर्ग ने एक खुला पत्र लिखकर दार्फुर की स्थिति के बारे में अपनी चिंताओं से राष्ट्रपति हु जिंताओ को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारी मेरे सम्पर्क में हैं और वे यह दलीलें दे रहे हैं कि सरकार स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनका केवल इतना कह देना ही काफी नहीं है।

श्री स्टीवेन स्पीलबर्ग के इस साहस भरे फैसले से प्रेरणा लेते हुए हालीवुड की चर्चित अभिनेत्री सुश्री थुर्मन ने 21 फरवरी को कहा कि श्री स्पीलबर्ग को अपनी चिंताओं में कुछ और चीजों को शामिल करना चाहिए। उनका इशारा तिब्बत में चीन के उपनिवेशवादी कब्जे और तिब्बती जनता के मानवाधिकारों की हालत की ओर था।

उन्होंने कहा, ''हालांकि चीन और वहां की जनता में ढेरों अच्छी बातें हैं, लेकिन चीन सरकार का मानवाधिकार का रिकार्ड भयावह है। मेरा मानना है कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने इनकी लंबी सूची बनाई होगी। स्टीवेन, कृपया इसपर थोड़ा और काम करें।''

तिब्बती बौद्ध धर्म के विद्वान एवं तिब्बती बौद्धभिक्षु बनने वाले प्रसिद्ध अमरीकी राबर्ट थुर्मन की पुत्री सुश्री उमा थुर्मन ने खासतौर पर तिब्बती बौद्धधर्मावलम्बियों की दुर्दशा पर चिंता जताई और कहा कि वहां मानवा धिकार के अनेक गंभीर मामले हैं।

अपने फैसलों से सुश्री थुर्मन और श्री स्पीलबर्ग उन हस्तियों में शामिल हो गये हैं जिन्होंने चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रहने पर चिंता जताई है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने घोषणा की थी कि वह बीजिंग में होने वाले ओलम्पिक

खेलों के किसी चरण में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा था कि तिब्बत में उनकी गहरी रुचि है।

चीन में धार्मिक उत्पीड़न, खासकर फालुन गोंग की साधना करने वालों पर किये जाने वाले उत्पीड़न की गंभीरता, के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पिछले वर्ष अगस्त में एथेंस में वैश्विक मानवाधिकार मशाल रिले का आयोजन किया गया था। इस माह के शुरू में नोबल पुरस्कार विजेताओं, राजनीतिज्ञों और ओलम्पिक एथलीटों ने चीन सरकार को एक खुला पत्र भेजा था, जिसमें यह अपील की गयी थी कि चीन सुडान को समर्थन देना बंद करे। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में आर्कबिशप डेसमंड टुटु, कलाकार मिया फैरो, एम्मा थॉम्पसन एवं जोआन्ना लुमले, गायक एंजेलिक किद्जो और ब्रिटिश नाटककार टॉम स्टॉपार्ड जैसी हस्तियां शामिल हैं।

मानवाधिकार संगठन 'ह्यूमैन राइट्स वाच ने दार्फुर के संबंध में प्रसिद्ध हस्तियों की चिंता का स्वागत किया है, लेकिन आगाह किया है कि जबतक चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन से नहीं निपटा जाता, तबतक बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

ह्यूमैन राइट्स वाच के मीडिया डाइरेक्टर मिन्की वार्डेन ने कहा, ''चीन में दमन के मामले बढ़ रहे हैं और ओलम्पिक प्रायोजक, सरकारें या दुनिया के नेता, खासकर वे लोग जो बीजिंग ओलम्पिक में भाग लेने की योजना बना रहे हैं अब कोई और बहाना नहीं बना सकते हैं। इन प्रभावशाली लोगों को चीन में मानवा धिकार की खराब स्थिति को सुधारने के लिए किये जा रहे अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहना होगा या मानवाधिकार के मुद्दे पर अपनी पराजय का कलंक झेलना होगा।''

पिछले वर्ष चीन के ग्रामीण इलाकों के हजारों कामगारों ने उस आवेदन पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें लिखा गया था, ''हम मानवाधिकारों का सम्मान चाहते हैं, न कि ओलम्पिक।'' चीन के 57 वकीलों, शिक्षाविदों, संपादकों, लेखकों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह ने हजारों कामगारों की इस मांग को अपना समर्थन दिया था।

प्रेस की आजादी से संबंधित एक संगठन 'रिपोटर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट–2008 में कहा है, ''अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के अलावा कोई भी यह बात मानने को तैयार नहीं है कि चीन सरकार ओलम्पिक खेल शुरू होने से पहले मानवाधिकारों के मामले में महत्त्वपूर्ण सुधार करेगी। हर बार एक पत्रकार या ब्लॉगर रिहा होता है तो दूसरा जेल में डाल दिया जाता है। चीन विरोधियों के लिए इस बार का ग्रीष्मकाल ओलंकिपक के कारण बहुत ही कष्टकारक साबित होने वाला है।''

उमा थुर्मान : तिब्बती जनता के मानवाधिकारों को समर्थन

आईओसी चीन के बचाव में उतरी

लेकिन 8 फरवरी को बीजिंग से जारी अपने एक बयान में अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने कहा है कि इतिहास साबित कर देगा कि चीन में मानवाधिकारों की स्थिति चिंताजनक होने के बावजूद बीजिंग शहर को वर्ष 2008 के ओलम्पिक खेलों की मेजबानी देने का उसका फैसला सही था।

अगले सप्ताह ओलम्पिक खेलों के शुरू होने में महज छह माह रह जाएंगे, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार के रिकॉर्ड को लेकर कुछ फुसफुसाहट अब भी जारी है। लेकिन आईओसी के संचार प्रमुख गिसेल्ले डेविस ने बीबीसी स्पोर्ट के साथ साक्षात्कार में कहा, ''हम बड़ी शिद्दत से मानते हैं कि यह सही फैसला था। हम अब भी अपने इस फैसले से उतना ही गौरवान्वित हैं, जितना फैसला करते वक्त कर रहे थे।''

एक शीर्ष मानवाधिकार कार्यकर्ता हु जिया की पिछले दिनों हुई गिरफ्तारी की वजह से आईओसी को अपने फैसले के बचाव में इस तरह का बयान देना पड़ा है। आई ओ सी ने चीन को ओलंपिक की मेजबानी की घोषणा करते समय दुनिया को आश्वासन दिया था कि इस जिम्मेदारी को पाकर चीन सरकार को अपने यहां मानवाधिकारों में सुधार करने का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन आईओसी इस सवाल का जवाब देने से कतरा रही है कि आज चीन में मानवा धिकार पहले के मुकाबले और खराब हैं। बीजिंग ओलंपिक निकट आने के साथ चीनी दादागीरी के बढ़ते जाने से ओलंपिक समित का नैतिक संकट भी बढ़ रहा है।

श्री स्टीवेन स्पीलबर्ग के इस साहस भरे फैसले से प्रेरणा लेते हुए हालीवुड की चर्चित अभिनेत्री सुश्री थुर्मन ने 21 फरवरी को कहा कि श्री स्पीलबर्ग को अपनी चिंताओं में कुछ और चीजों को शामिल करना चाहिए। उनका इशारा तिब्बत में चीन के उपनिवेशवादी कब्जे और तिब्बती की जनता के मानवाधिकारों की हालत की ओर था।

तिब्बत मुक्ति–साधना का तूफान पूरे तिब्बत में फैला, दुनिया की आंखें खुलीं

10 मार्च, से तिब्बत में उठी जनक्रान्ति और चीनी दमन का तिथिवार विवरण–2

इस साल 10 मार्च के दिन तिब्बती जनक्रान्ति की 49वी वर्शगांठ के मौके पर तिब्बत की राजधानी ल्हासा में भुरू हुए प्रद□ान देखते–देखते पूरे तिब्बत में फैल गए। इन प्रद□ानों को दबाने के लिए चीनी सेना और पुलिस की गोलियों से 209 तिब्बतियों के मारे जाने की पुश्टि हो चुकी है। इन प्रद□ानों के बारे में 'तिब्बत–दे□ा' के पिछले अंक में तिथिवार जानकारी देनी भुरू की गई थी। प्रस्तुत है उससे आगे का विवरण :

सेंट्रल नेशनेलिटीज़ यूनिवर्सिटी, बीजिंग के 100 से अधिक तिब्बती विद्यार्थियों ने आंदोलन में मारे गये तिब्बतियों के सम्मान में रतजगा किया। तिब्बत में हाल के प्रदर्शनों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों ने तिब्बती जनता के समर्थन में वैसी ही साहसिक भूमिका निभाई जैसे 20 वर्ष पूर्व 1988 के ल्हासा प्रदर्शनों में तिब्बती छात्रों ने भूमिका थी।

17 मार्च, 2008: गोंगकार में प्रद□ान

न्गाबा काउंटी के न्गातू भिक्षुणी मठ की भिक्षुणियों ने स्थानीय तिब्बतियों के साथ मिलकर 16 मार्च के विरोध प्रदर्शन में मारे गये लोगों के शवों के साथ प्रदर्शन किया।

सेंट्रल नेशनेलिटीज यूनिवर्सिटी, बीजिंग के 100 से अधिक तिब्बती विद्यार्थियों ने आंदोलन में मारे गये तिब्बतियों के सम्मान में रतजगा किया।

तिब्बत में हाल के प्रदर्शनों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों ने तिब्बती जनता के समर्थन में वैसी ही साहसिक भूमिका निभाई जैसे 20 वर्ष पूर्व 1988 के ल्हासा प्रदर्शनों में तिब्बती छात्रों ने भूमिका थी।

तोएलुंग देचेन काउंटी में 70 गिरफ्तार

तोएलुंग देचेन काउंटी के धिंगखा मठ के भिक्षुओं और सामान्य तिब्बती नागरिकों ने भी प्रदर्शन किया, जिसमें 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से कुछ को 120 युआन की जुर्माना राशि लेकर छोड़ दिया गया, जबकि अन्य लोगों को 1220 युआन की जुर्माना राशि के भुगतान के बाद अप्रैल के शुरू में रिहा किया गया।

गिरफ्तार किये गये 70 लोगों में से 12 भिक्षुओं और पांच सामान्य नागरिकों को यह कहा गया है कि उनकी सजा की घोषणा बाद जल्द ही की जाएगी।

18 मार्च, 2008

ल्हासा में आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से शहर में चप्पे–चप्पे पर टैंकों और सैन्य वाहनों की गश्त जारी रही। 15 मार्च से शुरू किये गये घर–घर तलाशी अभियान के दौरान शहर के पूर्व राजनीतिक बंदियों और संदिग्ध तिब्बतियों को निरंकुश तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, आंदोलन को कुचलने के लिए चीनी अधिकारियों ने उनके परिजनों को भी हिरासत में लिया।

19 को गोलीबारी में मौतः गांसू प्रांत के माचू काउंटी में कल से शुरू हुए आंदोलन को कुचलने के लिए पीएपी के जवानों ने गोलीबारी की जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 19 लोगों की मौत हो गयी। विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से भिक्षुओं को रोकने के लिए आसपास के मठों को सील कर दिया गया। इसी प्रांत के **सांगचु काउंटी** के **लाबरांग** में प्रदर्शनकारियों ने चुशुल जेल में 17 वर्ष से सजा काट रहे राजनीतिक बंदी जिगमे ग्यास्तो की रिहाई की मांग की।

सिचुआन प्रांत की कारजे काउंटी में कल शुरू हुए आंदोलन में कम से कम चार लोगों के मारे जाने और 15 के घायल होने की सूचना है। प्रदर्शन में 400 लोगों ने हिस्सा लिया।

उधर **सिचुआन प्रांत की सेरथार काउंटी** में भी विभिन्न स्थानों पर जोरदार प्रदर्शन हुए। इस दौरान तिब्बती ध्वज भी लहराए गए।

चिंघाई प्रांत की **क्येगुदो काउंटी** स्थित युलशुल मिडल स्कूल के करीब 400 छात्रों ने चीनी ध्वज को नोंचकर हटा दिया और प्रदर्शन किये। चीनी सैनिकों ने स्कूल परिसर को चारों ओर से घेर लिया। स्कूल के कर्मचारियों और शिक्षकों को यह सख्त हिदायत दी गयी कि इस घटना का जिक्र स्कूल के बाहर किसी से भी नहीं किया जाना चाहिए। बाद में यह भी निर्देश दिया गया कि ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक के आयोजन की समाप्ति तक स्कूल के कर्मचारियों और छात्रों का इधर–उधर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।

चाम्दो की गोंजो काउंटी में **सा न्गेन गांव** के तिब्बतियों ने विभिन्न जगहों पर हुए प्रदर्शनों में भाग लिया। लेकिन इस बारे में विस्तृत ब्योरा नहीं मिल पाया है।

19 मार्च, 2008

ल्हासा की जेलें ठुंस गईं: **ल्हासा** में चीनी सैनिकों ने सभी रिहाइशी परिसरों के मुख्य प्रवेश द्वारा सील कर दिये। प्रत्येक रात सैनिकों ने घरों की छानबीन की और वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जो परिवार के सदस्य नहीं थे और उस घर में रुके थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त पहचान पत्र वालों को भी नहीं बख्शा गया। चीनी सैनिक

यह मानते रहे कि घर में रुके अतिरिक्त सदस्य ने प्रदर्शन में कहीं न कहीं भाग अवश्य लिया है। इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों की वजह से ल्हासा की जेलों में तिल रखने की जगह नहीं बची।

ल्हासा में विरोध प्रदर्शनों का दायरा और आकार जैसे–जैसे बढ़ता रहा, वैसे–वैसे पीएपी के जवानों का शिकंजा कसता गया और सख्ती बढ़ती गयी। बाद में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के जवानों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई, ताकि आंदोलन को यथाशीघ्र कुचला जा सके।

तिब्बत के सीमाई क्षेत्र के चारों ओर चीनी सेना का सख्त पहरा और अधिक बढ़ गया ताकि बाहरी लोग तिब्बत में न प्रवेश कर सकें।

सिचुआन प्रांत में बारखाम काउंटी स्थित स्थानीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने 17 और 19 मार्च को अपने स्कूल पर तिब्बती ध्वज फहराए।

सिचुआन प्रांत की ज़ोगे काउंटी स्थित **जाम–मेई मठ** के भिक्षुओं के नेतृत्व में स्थानीय समयानुसार रात साढ़े आठ बजे आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें 300 से अधिक भिक्षुओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन के मुख्यालय और स्थानीय सैन्य शिविर पर लहरा रहे चीनी ध्वज को उतार लिया और 'परमपावन दलाई लामा जिन्दाबाद' और 'तिब्बत स्वतंत्र देश है' जैसे नारे लगाए। 22 मार्च को भिक्षुओं का वेश धारण कर सैनिकों ने आठ नागरिकों को गिरफ्तार किया और उनकी पिटाई भी की।

20 मार्च, 2008

3 मरे, 10 घायल – घायलों का इलाज नहीं : सिचुआन प्रांत के सेरथार काउंटी के तीन शहरों में कड़ी सैन्य सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अनेक स्थानों पर आंदोलन हुए। इन प्रदर्शनों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है। इसी काउंटी के फुवु शहर के सेरा मठ के प्रदर्शनकारी भिक्षुओं पर पीएपी के जवानों ने गोलीबारी की। प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में तीन भिक्षुओं की मौत हो गयी और दस घायल हुए। घायलों के इलाज की मनाही के कारण इन घाययलों को चीनी अस्पतालों में भर्ती नहीं कराया जा सका।

पेमा काउंटी के चाकरी, दो–घो, प्रोंगमा शहरों के भिक्षुओं और आम नागरिकों ने भी आज प्रदर्शन किया। **मारखाम काउंटी के त्सो–न्गा** शहर में रहने वाले तिब्बतियों ने भी प्रदर्शन किये, लेकिन इनका विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं हो सका। उधर, इसी काउंटी के रुशोए शहर से 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

बारखाम काउंटी के त्सो दुन कीर्ति मठ में वार्षिक समारोह 'मोनलाम छम' पर चीनी अधिकारियों ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। मठ के करीब 40 भिक्षु प्रतिबंध को लेकर शिकायत करने स्थानीय प्रशासन के मुख्यालय पहुंचे तो वहां भिक्षुओं और स्थानीय अधिकारियों में विवाद हो गया।

मारखाम काउंटी के **न्गुलरु दोपा और दोगो रुवा** सहित विभिन्न गांवों में प्रदर्शन कर रहे 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें मारखाम काउंटी जेल भेज दिया गया। उधर सिचुआन प्रांत की **ज़ामथांग काउंटी के दोतोए** शहर में तिब्बतियों और भिक्षुओं ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन चीनी सैनिकों ने भारी संख्या में आकर इसे तुरंत कुचल दिया।

चिंघाई प्रांत की पेमा काउंटी में चीनी दिशानिर्देशों के विरुद्ध लोगों ने प्रदर्शन किया और चीन एवं तिब्बत के बीच बातचीत के ठोस परिणाम की मांग की।

21 मार्च, 2008

भिक्षुओं के वे□ा में चीनी सैनिक : पीपुल्स सिक्यूरिटी ब्यूरो के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, 19 मार्च से चीनी सैनिकों ने भिक्षुओं का वेश धारण करना शुरू कर दिया। इससे उनका दो मकसद हल हो रहा था– पहला, वे भिक्षुओं के वेश में तिब्बतियों को समझा रहे थे कि स्थिति अब सामान्य हो गयी है और दूसरा, भिक्षु के वेश में उन्हें लोगों तक आसानी से पहुंचने और प्रदर्शनों को कुचलने के लिए आवश्यक गुप्त सूचनाएं हासिल करने में आसानी हो रही थी।

इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि चीनी सेना की चार यूनिटें भिक्षुओं का वेश धारण कर जानकारियां इकट्ठा करने वाली नीति पर काम कर रही थीं। ये यूनिटें इस प्रकार हैं–

1. बोर्डर सिक्यूरिटी (पीएलए)
2. कोआर्डिनेशन यूनिट (पीएलए)
3. मिलिट्री इंटेलीजेंस (पीएलए)
4. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी – 52 डिविजन

मा□ल–लॉ जैसी हालत : कहने को तो चीन ने ल्हासा और अन्य जगहों पर मार्शल लॉ की अनुमति नहीं दी, लेकिन जमीनी हकीकत यही रही कि तिब्बत में परोक्ष रूप से मार्शल लॉ लागू रहा। तिब्बत में चीनी सेना की विभिन्न वाहिनियां तैनात की गयीं और शाम सात बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता था। बिना राशन कार्ड के पाये गए

सिचुआन प्रांत के सेरथार काउंटी के तीन शहरों में कड़ी सैन्य सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अनेक स्थानों पर आंदोलन हुए। इन प्रदर्शनों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है। इसी काउंटी के फुवु शहर के सेरा मठ के प्रदर्शनकारी भिक्षुओं पर पीएपी के जवानों ने गोलीबारी की। प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में तीन भिक्षुओं की मौत हो गयी और दस घायल हुए। घायलों के इलाज की मनाही के कारण इन घाययलों को चीनी अस्पतालों में भर्ती नहीं कराया जा सका।

तिब्बतियों को ल्हासा से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया गया।

20 और 21 मार्च को ल्हासा में अनेक तिब्बतियों को निरकुंश तौर पर गिरफ्तार किया गया।

सिचुआन प्रांत की कारजे काउंटी में करीब 50 भिक्षुणिओं और भिक्षुओं के अलावा बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने कल और आज विरोध प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य हाल के प्रदर्शनों के दौरान मारे गये तिब्बतियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना था।

*चिंघाई प्रांत की **त्सेगोर थांग** काउंटी स्थित **एत्सोक मठ** के भिक्षुओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और मठ की छत और पीछे स्थित पहाड़ी चोटी पर से चीनी ध्वज नोंचकर हटा दिया गया और उनके स्थान पर तिब्बती ध्वज फहराए गये। चीनी सैनिकों ने मठ परिसर को चारों ओर से घेर लिया। उनलोगों ने मठ के लामाओं को आंदोलन समाप्त कराने के लिए मजबूर किया। भिक्षुओं को यह भी हिदायत दी गयी कि इस बात का जिक्र मठ के बाहर के लोगों से नहीं किया जाए।*

22 मार्च, 2008

चिंघाई प्रांत की दारलाग काउंटी स्थित **तोएमा और मेयमा** गांवों में 200 प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। नागरा टाउनशिप के चार गांवों द्रुलचू, खोलत्सा थांग, लुग्याल और न्यामो के तिब्बती नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनके सहयोग में क्यारेंग टाउनशिप के तिब्बती भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती ध्वज लहराए। उनके हाथों में दलाई लामा और पंचेन लामा की तस्वीरें भी मौजूद थीं। आंदोलनकारियों का कारवां आगे बढ़ता रहा और जब यह चेंत्सा काउंटी मुख्यालय के पास पहुंचा तो उसमें लेचेन, मारखुथांग और बारत्सा गांवों के लोग भी शामिल हो गये। चीनी अधिकारियों ने कुछ प्रतिष्ठित लामाओं को इस बात के लिए दबाव भी दिया कि वे आंदोलन समाप्त करने में सहयोग करें, लेकिन आंदोलन तीन बजे तक जारी रहा।

हुनान प्रांत से 50 ट्रकों में भरकर चीनी सैनिक आज चेंत्सा काउंटी इलाके पहुंचे। चीनी सैनिकों की भारी भरकम संख्या के बावजूद **मिरी गोंगमा, मिरी शोल्मा, लोवा और त्सुलशिंग गांवों** में आज प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान **लोखोग गांव** से चार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और वहां प्रदर्शन बंद करा दिया गया।

चिंघाई प्रांत के धारथांग मठ के प्रमुख कारवांग न्यीमा रिम्पोछे को चीनी सेना द्वारा उत्पीड़ित न करने की मांग को लेकर पालयुल गांव स्थित पहाड़ी पर करीब 500 भिक्षुओं और आम नागरिकों ने धरना दिया। लोगों ने यह भी मांग की कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अमरीका और अन्य देश मौजूदा तिब्बत–चीन विवाद के समाधान के लिए हस्तक्षेप करें।

रात करीब नौ बजे, चिंघाई प्रांत की **त्सेगोर थांग** काउंटी स्थित **एत्सोक मठ** के भिक्षुओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और तिब्बत की आजादी के समर्थन में नारेबाजी की। मठ की छत और पीछे स्थित पहाड़ी चोटी पर से चीनी ध्वज नोंचकर हटा दिया गया और उनके स्थान पर तिब्बती ध्वज फहराए गये।

चीनी सैनिकों ने घटनास्थल पहुंचकर मठ परिसर को चारों ओर से घेर लिया। उनलोगों ने मठ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और लामाओं को आंदोलन समाप्त कराने के लिए मजबूर किया। भिक्षुओं को यह भी हिदायत दी गयी कि इस बात का जिक्र मठ के बाहर के लोगों से नहीं किया जाए।

23 मार्च, 2008

चीनी सैनिकों ने **गोंजो काउंटी** से कुछ तिब्बतियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इसका विस्तृत ब्योरा नहीं मिल पाया है।

24 मार्च, 2008

हालांकि तिब्बत में चल रहे आंदोलन में चीनी दमन के तहत मारे गये तिब्बतियों की संख्या 140 हो चुकी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने इनमें से 40 मृतकों के नाम जारी किये हैं। मृतकों में से अनेक के शव उनके परिजनों को सौंपने के बजाय चीनी प्रशासन ने अपने कब्जे में रख लिए हैं। इस वजह से मृतकों की सूची बनाने में भी परेशानी आई है।

चीनी सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने **सिचुआन प्रांत की कारजे काउंटी** में प्रत्येक घर की गहन तलाशी ली। **सेरशुल काउंटी** में तलाशी के दौरान चुगात्सांग परिवार से परमपावन दलाई लामा की 70 तस्वीरें और उनके भाषण की तीन सीडी बरामद की गयी। इस परिवार के सभी सदस्यों को कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किये जाने के बाद घर की तलाशी ली गयी।

23 और 24 मार्च को ल्हासा नगर निगम के तहत **तोएलुंग देचेन** काउंटी से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

25 मार्च, 2008

चीन विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले मठों – सेरा, द्रेपुंग और गंदेन में चीनी सेना और पीएपी के जवानों ने पानी, बिजली, खाद्यान्न और स्वास्थ्य सुविधाओं को रोक दिया है।

ल्हासा के रामोचे मठ में 14 मार्च से ही चीनी सैनिकों की सख्त उपस्थिति हो गयी थी। सैनिकों ने मठ के प्रवेश और निकास मार्गों पर सख्त घेरा डाल रखा था। कड़े प्रतिबंधों की वजह से खाद्यान्न और पानी की आपूर्त्ति सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। 23 मार्च को थोकमेयी नामक एक भिक्षु की मौत हो गयी। बीच–बीच में चीनी सैनिकों द्वारा मठ परिसरों के भीतर आंसू गैस के गोले भी फेंके जाते रहे हैं।

अगले अंक में जारी .....